Newspaper Clips
May 13, 2012

Pioneer ND 13/05/2012 P-7

IITs oppose single entrance exam from next year

PNS ■ NEW DELHI

Against the backdrop of sustained opposition to the proposed single entrance test for admission to engineering programmes, the IIT Council met on Saturday and is understood to have insisted on holding the test from 2014, instead of next year.

The Council, which met under the chairmanship of HRD Minister Kapil Sibal, is also understood to have discussed the possibility of preparing the merit list without taking into account the candidates' performance in board examinations.

A final decision will be taken at the joint meeting of Councils of IITs and NITs on May 28, HRD ministry sources said. They said only IIT-Guwahati has fully supported the proposal of a single entrance test with weightage to marks in the school boards.

The aim is to hold the test in a new format from 2013 onwards under which a ranking list will be prepared based on Class XII results with 40 per cent weightage to be given after normalisation of marks, 30 per cent to the main test and 30 per cent to the advanced test.

The test will replace the existing IIT-JEE and the All India Engineering Entrance Examination (AIEEE). Several IIT senates, especially those of the seven old IITs, had objected to this format.

The faculty federation had also expressed stiff opposition to the proposal and insisted that the senates should have the final say on this issue. Sources said the issue of factoring the plus-two boards results were yet to be sorted out.

While boards across the country are expected to declare their results almost simultaneously under the new format, a section feels this would be highly unlikely. During the meeting, the IITs are understood to have opted to retain the existing format of JEE for the year 2013. They have also stressed on giving thrust on the advance test for preparing the results.

Asian Age ND 13/05/2012 P-3

No decision yet on common entrance

NITIN MAHAJAN
NEW DELHI, MAY 12

The proposed common national examination for science and engineering for Central institutes, scheduled for implementation from 2013, may be delayed as the IIT council meeting on Saturday ended without taking any concrete decision on the issue. The councils are pushing for an year's delay in the implementation of the single entrance test and are insisting on holding the test from 2014.

At Saturday's meeting, held under the chairmanship of HRD minister Kapil Sibal, the IITs are understood to have opted to retain the existing format of JEE for the year 2013. Sources stated that another joint meeting of the IIT and NIT councils has been scheduled for May 28 where

IIT COUNCIL MEET

these issues will be discussed again and a final decision taken. Earlier this meeting was scheduled to be held on April 14 but was deferred indefinitely after the government came under attack from the All India IIT Faculty Federation which has continued its opposition to the proposed changes to the existing IIT-JEE entrance examination pattern.

The proposed test will replace the existing IIT-JEE and the All India Engineering Entrance Examination.

Sources said the indecision on the proposed single entrance examination means the entire process could take several months and could push back the date of implementation of the entrance test further.

It is understood that at the meeting the issue was discussed again, however, it was pointed out that senates of several IITs had continued to oppose the proposed single entrance test proposal.

The council is also understood to have discussed the possibility of preparing the merit list without taking into account the candidates' performance in board examinations.

Hindustan Times ND 13/05/2012 p-8

IIT council meet deliberates on IIT-JEE exam

NEW DELHI: The IIT council meeting, chaired by HRD minister Kapil Sibal on Saturday, deliberated on the recommendation of various senates on the IIT-JEE exam. The final announcement will be made after the Joint Council's meet on May 28. Sources said a proposal to change the exam pattern may not be implemented from 2013 due to opposition from the IITs.

Hindustan ND 13/05/2012 P-4

आईआईटी परिषद में भी नहीं बनी सहमति

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस

- परिषद बैठक में पुराने आईआईटी को रास नहीं आया सिब्बल का प्रस्ताव
- कई आईआईटी ने कहा, जेईई के जरिये ही देंगे 2013 में दाखिला

आईआईटी तथा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रस्तावित कॉमन एंट्रेंस के 2013 से लागू होने के आसार और कम हो गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा शनिवार को बुलाई आईआईटी परिषद की बैठक में भी पुराने आईआईटी ने साफ कह दिया कि वे अगले साल से इसे लागू नहीं कर पाएंगे। शुक्रवार को हुई बैठक में भी इनका यही रुख थे।

सिब्बल की अध्यक्षता में हुई आईआईटी परिषद की बैठक में शामिल एक शीर्ष अधिकारी ने 'हिन्दुस्तान' से कहा कि कॉमन एंट्रेंस पर अभी तक कोई आमराय नहीं बनी है। अब इस महीने की 28 तारीख को मंत्रालय दुबारा बैठक करेगा जिसके बाद ही कोई फैसला होने की उम्मीद है। अगली बैठक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी एनआईटी को भी बुलाया गया है। अधिकारी ने कहा कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रवेश परीक्षा का ढांचा जटिल नहीं बल्कि आसान हो। कई सदस्यों ने सवाल उठाए कि अलग-अलग राज्यों के बोर्ड से पढ़कर आने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा में उनके अंको का वेटेज यानी वरीयता किस फार्मूले पर दी जाए।

उल्लेखनीय है कि सिब्बल चाहते हैं कि सभी आईआईटी तथा केंद्र सरकार के अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 2013 से ही कॉमन एंट्रेंस की प्रणाली अपनाई जाए, जिसमें 12वीं कक्षा के अंकों को भी वरीयता मिले।

Amar Ujala ND13/05/2012 P-11

आईआईटी कौंसिल की बैठक बेनतीजा

अमर उजाला ब्यूरो

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पर फैसला 28 तक टला

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग के लिए सिंगल प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर आईआईटी कौंसिल की बैठक में मुखर विरोध के चलते कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब इसी मुद्दे पर 28 मई को आईआईटी व एनआईटी कौंसिल की संयुक्त बैठक होगी। इसके बाद इस परीक्षा पर सरकार अंतिम फैसला लेगी।

दिल्ली आईआईटी परिसर में शनिवार को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंजीनियरिंग के लिए सिंगल प्रवेश परीक्षा कराने के मुद्दे पर कुछ आईआईटी के निदेशकों ने कहा कि उनके यहां फैकल्टी व सीनेट अभी भी विरोध पर अड़े हैं। विशेष रूप से कानपुर, दिल्ली व मुंबई आईआईटी में फैकल्टी एसोसिएशन के पदाधिकारी चाहते हैं कि परीक्षा कम से कम एक साल के लिए टाली जाए तथा इसका आयोजन 2014 से पहले न हो। यही नहीं, वे परीक्षा के पैटर्न तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांक को 40 फीसदी वरीयता दिए जाने के पक्ष में भी नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 28 मई को आईआईटी तथा एनआईटी कौंसिल की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दोनों संस्थाओं की कौंसिल से विचार विमर्श के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

Dainik Bhaskar ND 13/05/2012 P-16

सिंगल इंजीनियरिंग टेस्ट 2013 से नहीं होगा

नई दिल्ली. देश में एकल इंजीनियरिंग टेस्ट कराने की मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल की मंशा वर्ष 2013 में परवान नहीं चढ़ेगी। शनिवार को कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में हुई आईआईटी कार्उसिल की बैठक में ज्यादातर आईआईटी ने इस मसले पर अपना विरोध जताया। अकेले आईआईटी गुवाहाटी ने 2013 से सिंगल टेस्ट और परीक्षा के प्रस्तावित प्रारूप का समर्थन किया। लिहाजा, अब यह माना जा रहा है कि एकल टेस्ट का प्रस्ताव 2014 तक के लिए टाल दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में ज्यादातर आईआईटी ने फैकल्टी और अन्य समूहों की चिंता का हवाला देते हुए वर्ष 2013 से बजाए एकल टेस्ट का प्रस्ताव जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाने का सुझाव दिया। सुझाव है कि इस पर अमल के लिए एक साल आगे बढ़ाकर 2014 पर फोकस करना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला 28 मई को होने वाली आईआईटी-एनआईटी कार्उसिल की साझा बैठक में ही होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आईआईटी की ओर से बोर्ड के अंकों को वेटेज देने के मसले पर विरोध सामने आया। 40 फीसदी वेटेज का विरोध करने के साथ अलग-अलग बोर्ड के अंक को नार्मलाइज करने के फार्मूला पर भी सवाल उठा।

सूत्रों ने माना कि बैठक में मौजूद कपिल सिब्बल ने भी आईआईटी की चिंता को माना। उन्होंने भी भरोसा दिया है कि वेटेज या फिर अलग से मेरिट लिस्ट तैयार करने की संभावना को लेकर फिर चर्चा होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 से एकल इंजीनियरिंग टेस्ट कराने के प्रस्ताव पर कई राज्यों के विरोध के बाद आईआईटी फैकल्टी ने खुलकर विरोध जताया था। इसके बाद फैकल्टी फेडरेशन को इस मसले पर चर्चा करके रिपोर्ट देने को कहा गया था। फैकल्टी प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ। इसके चलते ही काउंसिल इस मसले पर आम राय नहीं बना पाई।

Dainik Bhaskar ND 13/05/2012 P-7

आईआईटी बनाएगा नए अध्यापकों के लिए अपग्रेडेशन कोर्स

पंकज कुमार पांडेय. नई दिल्ली

देश के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में नियुक्त किए गए नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का नॉलेज अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके लिए देश में आईआईटी नया मास्टर कोर्स डिजाइन करेगी। योजना के तहत युवा अध्यापकों को पहले मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी के लिए प्रेरित किया जाएगा। नए ग्रेजुएट टीचर्स को नियुक्त करके काम चलाने वाले निजी इंजीनियरिंग संस्थानों को नॉलेज अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग से जोड़ने की कार्ययोजना 12वीं योजना के लिए बनाई गई है।

कार्ययोजना के प्रपत्र में कहा गया है कि 12वीं योजना में आईआईटी के जरिए ऑनलाइन मास्टर डिग्री कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। नार्मल टीचिंग ड्यूटी में कोई खलल न पड़े इसके लिए मास्टर कोर्स के वीडियो लेक्चर्स का इंतजाम होगा। युवा अध्यापकों की ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन को साथ-साथ संचालित किया जाएगा। दरअसल निजी क्षेत्र के जरिए उच्च शिक्षा में विस्तार की संभावना तलाश रही सरकार बारहवीं योजना में प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी खास फोकस कर रही है। मानव संसाधन मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि देश में योग्य फैकल्टी की कमी है। इसलिए अध्यापकों के लिए नॉलेज अपग्रेडेशन की योजना बनाई गई है।

करीब 30 हजार फैकल्टी होगी तैयार

अनुमान है कि हर साल 6 से सात हजार युवा फैकल्टी को शैक्षणिक रूप से अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से 12 वीं योजना में करीब 30 हजार कॉलेज फैकल्टी प्रशिक्षित होंगी।आईआईटी व अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों की करीब 1500 फैकल्टी शाम को और वीकेंड में नए कोर्स के लिए अपनी सेवा देंगे। इसके लिए अतिरिक्त मानदेय की योजना का खाका भी तैयार किया जा रहा है। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि आईआईटी फैकल्टी इन युवा फैकल्टी को मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी के लिए प्रेरित करें।

निजी क्षेत्र के संस्थानों से कदमताल

मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि फैकल्टी की कमी की वजह से निजी इंजीनियरिंग कॉलेज नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों को नियुक्त करने को बाध्य होते हैं। इन नए टीचर्स को ट्रेनिंग और नॉलेज अपग्रेडेशन की जरूरत है। मौजूदा संस्थानों में ट्रेनिंग देने की क्षमता नहीं है। 12वीं योजना की कार्ययोजना में कहा गया है कि निजी कॉलेजों के लिए यह भी व्यावहारिक नहीं है कि वे इन नए टीचर्स को लंबी ट्रेनिंग या नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए भेज सकें। लिहाजा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जा रहा है।

दोहरी डिग्री का भी प्रस्ताव

एक अन्य प्रस्ताव यह भी है कि एक नया तीन साल का प्रोग्राम दोहरी मास्टर डिग्री के लिहाज से तैयार किया जाए। इसके तहत डोमेन एरिया में एमटेक डिग्री दी जाएगी। साथ ही शैक्षणिक कौशल और अध्यापन विधा में मास्टर डिग्री दी जाएगी।

यह भी है योजना

निजी कॉलेजों को एआईसीटीई के जरिए गवर्नेंस में पारदर्शिता बढ़ाने को कहा जाएगा। संस्थानों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नए कॉलेजों को शैक्षणिक स्वायत्तता दी जाएगी।

12 May 2012 | Hindustan Times (Mumbai) | HT Correspondent htmetro@hindustantimes.com

HC nod for appointment of Pune varsity vice chancellor

Dismisses petition challenging state's selection procedure to appoint heads of universities

MUMBAI: The Bombay high court, on Friday, dismissed a petition challenging the state's selection process for vice chancellors, paving the way for the appointment of a new VC for the of Pune. MUMBAI: The Bombay high court, on Friday, dismissed a petition challenging the state's selection process for vice chancellors (VC), paving the way for the appointment of a new VC for the of Pune.

Thane-based social activist, Suresh Patilkhede, had approached the HC challenging the validity of the Maharashtra Universities (Amendment) Ordinance, 2009.

The Ordinance, which amended certain provisions of the Maharashtra Universities Act, 1994, provides for nomination of a search committee to shortlist candidates for the VC'S post. The Governor then selects one of the short-listed candidates.

Patilkhede contended that the process went against the regulations of the Universities Grant Commission (UGC). He further contended the selection mechanism was illegal and lacked basic sanctity of law.

A division bench of chief justice Mohit Shah and justice Niteen Jamdar, however, did not find anything wrong with the process. "The respondents have acted in consonance with the provisions of the Maharashtra Universities Act," the judges observed. The HC also turned down a request by the petitioner to stay the selection process till they moved Supreme Court.

The state authorities, on January 6, had said that they would not continue with the selection process till the petition was pending.

On Friday, after the judgement was pronounced, advocate VB Tiwari, who represented the petitioner, sought a stay based on that statement.

Girish Kulkarni, representing of Pune, opposed the request, stating that the VC'S post has been vacant for eight months now, and the was in urgent need of a VC. The 's VC, RK Shevgaonkar, left to join the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi as director. The judges accepted this and said that the appointment could not be delayed further..

The petitioner's counsel, Anil Anturkar, had argued that UGC regulations would prevail over the Maharashtra Universities Act. The HC, however, held that UGC guidelines, at the most, could be termed as subordinate legislations and could not override the provisions of a legislation enacted by the State Legislature.

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and protected by applicable law.